गांवों-कस्बों में लगेंगे 12 हजार करोड़ के उद्योग

हिन्दुस्तान खास

राज्य मुख्यालय | **हेमंत श्रीवास्तव**

गांवों व कस्बों में कृषि आधारित उद्योग धंधा लगाने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार की एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोग न्यूनतम दर पर लोन लेकर अपना उद्योग लगा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमवीएस रामीरेड्डी को राज्य का नोडल अधिकारी बनाया है। रामीरेड्डी 10 विभागों से समन्वय करते हुए ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की वृहद कार्ययोजना तैयार करेंगे।

तीन साल में यूपी ले सकता है 12 हजार करोड़: केंद्र सरकार ने इसके संबंध में मंगलवार को भारत सरकार के सचिव ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर मंथन किया। इस फंड से राज्य अगले तीन साल में उद्योग स्थापित करने वालों को 12 हजार करोड़ रुपये की धनराशि से ऋण दिला सकता है। फंड का मूल उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाना है।

पलायन रुकेगा: नोडल अधिकारी द्वारा राज्य के 10 विभागों खासकर कृषि उद्योग, उद्यान, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता, एमएसएमई के उच्चाधिकारियों के साथ जल्द ही भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए वृहद कार्ययोजना बनाई जाएगी। योजना से गांवों से पलायन भी रुकेगा।

यूं मिलेगा उद्यमियों को कर्ज

सहकारी संस्थाएं: 4 फीसदी पर ऋण, इसमें तीन फीसदी ब्याज अनुदान यानी ब्याज एक फीसदी

निजी संस्था-उद्यमी: छह फीसदी पर ऋण, इसमें तीन फीसदी अनुदान यानी तीन फीसदी पर ब्याज

ऋण सीमा: अधिकतम 30 लाख से दो करोड़ तक

10

विभागों से समन्वय करते हुए ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे

03

सालों तक प्रदेश में केंद्र सरकार के इस धनराशि से उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा

फूड प्रोसेसिंग व डेरी को बढ़ावा

योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, डेयरी, मछली पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए लोन दिए जाने की व्यवस्था है।